

72वें गणतंत्र दिवस की झलकियां | पेज 17 से 20

» वर्ष: 01, अंक:15

» 1 से 15 फरवरी 2021, नि:शुल्क

न्यू इंडिया समाचार



2021 की सबसे बड़ी उम्मीद साकार

कोविड
वैक्सीन

आत्मनिर्भर भारत की अमिट पहचान बनी स्वदेशी वैक्सीन सबसे पहले एम्स, दिल्ली के फ्रंटलाइन वर्कर मनीष कुमार को लगी

विश्व रेडियो दिवस

पूरी दुनिया 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था कि रेडियो कार्यक्रम का अनुभव उनके लिए खास है, क्योंकि इससे लोगों के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ है। इस बार रेडियो दिवस की थीम है

EVOLUTION, INNOVATION, CONNECTION



“ मैं रेडियो जगत में काम करने वाले लोगों की रचनात्मकता और समर्पण को सलाम करता हूँ, हमारा मनोरंजन बनाए रखने और जानकारी देते रहने के लिए आपका धन्यवाद। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ”

संपादक

कुलदीप सिंह धतवालिया,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक

संतोष कुमार

विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक

विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:

सत्येन्द्र प्रकाश,
महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड
कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स
प्राइवेट लिमिटेड, बी-278,
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड
कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय
तल, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

डिजाइनर

श्याम शंकर तिवारी



आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

लगने लगा उम्मीद का टीका



आवरण कथा

कोरोना से लड़ाई का आखिरी चरण, महज 10 महीने में ईजाद हुई
स्वदेशी वैक्सीन से स्वस्थ होगा भारत। पेज 06-12

फ्लैगशिप योजना...
नई तकनीक से होगा सबको
आवास का सपना साकार

पेज 15-16

वंदे भारत ट्रेन...
आत्मनिर्भर भारत:
स्वदेशी से गति की
उड़ान भरता देश



भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिक हो रही
है, जानिए वंदे भारत ट्रेन के बारे में जो है
गति, सुविधा और सुरक्षा की पहचान

पेज 28-30

समाचार-सार

देश की प्रमुख खबरें। पेज 4-5

वैक्सीन ईजाद करने में अग्रणी श्रेणी में रहा भारत

नीति आयोग के सदस्य(स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल से विशेष बातचीत। पेज 13-14

72वें गणतंत्र दिवस की झलकियां | पेज 17-20

एक देश, एक सुविधा, एक व्यवस्था

लोगों का जीवन स्तर सुधार रही हैं विभिन्न योजनाएं। पेज 21-23

युवा उत्साह और आकांक्षाओं से लैस होगा नया भारत

युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही सरकार। पेज 24-26

भारत अब सेकेंड के अरबवें हिस्से को मापने में सक्षम

नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल से मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। पेज 27

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा

कैबिनेट के फैसले। पेज 31

भारत से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले 'सीमांत गांधी'

कहानी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खां की। पेज 35

पर्यावरण बचाने की अनोखी पहल

कहानी बदलते भारत की। पेज 36

मिशन आत्मनिर्भरता में जुटे प्रवासी भारतीय

देश की संस्कृति और गौरव को अपने साथ ले जाकर दुनिया भर में भारत को स्थापित
करने वाले प्रवासी और भारतीय मूल के लोग अब मिशन आत्मनिर्भरता के जरिए
अपनी माटी का कर्ज चुकाने को आतुर हैं। पेज 32-34

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में आपकी उम्मीद साकार हुई। 16 जनवरी अब सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे हर आपदा में उदाहरण के तौर पर बताया जाएगा। पहले कभी इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान कभी नहीं चलाया गया है। दुनिया में सौ से ज्यादा देश हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ से कम है, और भारत कोरोना टीकाकरण के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है।

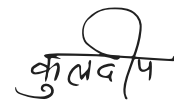
भारत की इस बड़ी सफलता के लिए वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग प्रशंसा के पात्र हैं ये सभी बीते कुछ महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। वैक्सीन बनाने में आमतौर से 7-8 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने अपना सामर्थ्य दिखाया और चंद महीनों में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर नया उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।

कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, सामाजिक संस्थाएं और यहां तक कि दुनियाभर में बसे प्रवासी भारतीय, सबने एकजुटता के साथ 'टीम इंडिया' की तरह काम कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। इस अंक में वैक्सीन के ईजाद होने से लेकर भविष्य की तैयारियां आवरण कथा बनी है।

ऐसे ही स्नेह और विश्वास के साथ आप अपने विचार और सुझाव हमें लिखते रहिए।

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003

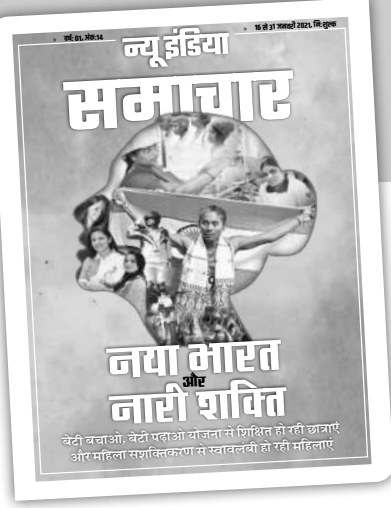
ईमेल- response-nis@pib.gov.in



(कुलदीप सिंह धतवालिया)



आपकी बात...



न्यू इंडिया समाचार का नवीनतम अंक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021 पढ़ने को मिला। यकीनन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। पत्रिका में हर क्षेत्र की उपलब्धियों का वर्णन और आवश्यक सकारात्मक जानकारी शामिल की गई है। न्यू इंडिया समाचार परिवार को नववर्ष के साथ जानकारी प्रदान करने के लिए कोटि-कोटि बधाई एवं सादर धन्यवाद।



विजय तिवारी vijaytiwari114@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार के पाठक होने के कारण मेरी व्यक्तिगत राय है कि कृपया महिलाओं के सशक्तिकरण पर अंक प्रकाशित करें। महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में अवसरों की समानता एवं स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक लेख दें।



gauripandey25@gmail.com

मुझे एक जनवरी की पत्रिका का अंक मिला। सरकार की दूरदर्शिता और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं संपादक महोदय का आभारी हूँ।



पूजराज सिंह बाला
poonjrajsinghbala@gmail.com



न्यू इंडिया समाचार के प्रकाशक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है आप ऐसे ही न्यू इंडिया समाचार के माध्यम से जनता को अति आवश्यक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करते रहेंगे।
के एन पाण्डेय panditkaushalpandey@gmail.com

आपकी यह पत्रिका मिली। देखकर ऐसा लगा कि यह तो गागर में सागर है। कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जिसकी जानकारी नहीं दी गई है। अत्यंत ही सुखद अनुभव हुआ है। आशा है कि आगे भी इसी तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी।
अनेक साधुवाद।



मानवेंद्र प्रतिहस्त
mpratihast@gmail.com

नए कृषि कानून के बारे में विस्तार से जानकारी, अटल की यादें, सौर ऊर्जा का बेहतर विकल्प, कोविड वैक्सिन की तैयारी, अर्थव्यवस्था की लगातार बेहतर होती स्थिति के बारे में दी गई जानकारी सराहनीय है।



kheemanandpenday1979@gmail.com

एक से 15 जनवरी 2021 की न्यू इंडिया समाचार पत्रिका मिली। 'नया भारत नया संकल्प' शीर्षक से समीक्षात्मक लेख अच्छा लगा, साथ ही पत्रिका में शामिल किए गए अन्य लेख प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक हैं। प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।



रचना कुलश्री
rachnauniyal79@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का प्रत्येक अंक मुझे पढ़ने के लिए मिल रहा है। 1 से 15 जनवरी का अंक प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण सामग्री पठनीय। विशेषकर आपकी जीवनशैली अब आयुर्वेदिक और कश्मीर पर आलेख एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार, बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। पत्रिका के सम्पादक और लेखकों को साधुवाद।



नरेश रोहिला
nareshrohila18@gmail.com

भारत बनेगा खिलौनों का ग्लोबल विनिर्माण हब, 'टॉयकाथॉन' लांच

अब भारत में ही नए और अनूठे प्रकार के खिलौनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने टॉयकाथॉन की शुरुआत की है। इस अभियान में छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप से जुड़े लोग एक मंच पर आकर नए-नए प्रकार के खिलौने और 'गेम' बनाने को लेकर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। भारत में अभी 80 फीसदी खिलौने आयात होते हैं, ऐसे में खिलौना विनिर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार देश में ही काम कर रहे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए आधा दर्जन मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ा गया है। इसके तहत 1



अरब अमेरिकी डॉलर वाले खिलौना बाजार को जोड़ते हुए 33 करोड़ छात्रों को इस नए कौशल से जोड़ने का भी खाका तैयार किया गया है। टॉयकाथॉन के विजेताओं को सरकार 50 लाख रु. तक का पुरस्कार भी देगी। इसके नतीजे 23-25 फरवरी को आएंगे।

पूरे देश में अब मिस्ड कॉल से होगी एलपीजी रिफिल बुकिंग

आम लोगों का जीवनयापन आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक



ऐसा कॉमन नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देते ही सिलेंडर बुक हो जाएगा। इंडियन ऑयल के ग्राहकों को 8454955555 नंबर पर यह सुविधा मिलेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में इस नंबर से रिफिल ही नहीं, नए कनेक्शन भी मिलेंगे। नए कनेक्शन वाली सुविधा का

विस्तार आने वाले समय में देश भर में किया जाएगा। आईवीआरएस पर मिस्ड कॉल की सुविधा से अब तत्काल बुकिंग होगी, ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड नहीं करना होगा और इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कॉल का शुल्क भी नहीं लगेगा। अब ऐसे ग्राहक जो बुजुर्ग हैं और आईवीआरएस से परिचित नहीं हैं, उनका भी जीवन सुगम होगा।

देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए पीएम-केयर्स की बड़ी पहल

देश भर में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पीएम-केयर्स फंड ने बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत



कोष (पीएम-केयर्स) से इसके लिए 201.58 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स स्थापित होंगे। इससे देश के 32 राज्यों-केंद्र

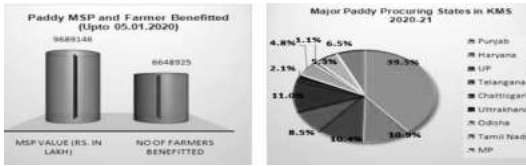
शासित प्रदेशों में 154.19 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्लांट लगाए जाएंगे। कोरोना के इस दौर में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एक बड़ी जरूरत है, ऐसे में पीएम-केयर्स की पहल ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

महज 1 साल में पूरे देश में 16% बढ़ी महिला पुलिसकर्मियों की संख्या



राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या में महज एक साल के भीतर 16 फीसदी की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। राज्यों में महिला कर्मियों की सबसे अधिक हिस्सेदारी के मामले में बिहार सबसे आगे आता है। यहां नागरिक पुलिस, जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस बल, विशेष सशस्त्र पुलिस बल और भारत रिजर्व बटालियन में कुल 25.3 फीसदी महिला कर्मी हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 19.15 फीसदी है।

एमएसपी पर धान की खरीद में 23.41 फीसदी की बढ़ोतरी



सरकार ने चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीते वर्ष की तुलना में इसमें 23.41% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष के 466.22 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल 20 जनवरी तक 575.36 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें अकेले पंजाब का योगदान 202.77 लाख मीट्रिक टन का है जो कुल खरीद का करीब 35.24% है। साथ ही देश में खाद्यान्न उत्पादन भी 25.154 करोड़ टन से बढ़कर 2019-20 में 29.665 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया जो अभी तक का सबसे अधिक है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 108629.27 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीदी की गई है। इससे लगभग 82.08 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

अब आम लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहे ई-संजीवनी और वेलनेस सेंटर

जब देश कोरोना की वजह से सामाजिक दूरी की अनिवार्यता का पालन कर रहा है, ऐसे में घर पर ही लोगों को सलाह और ईलाज उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ई-संजीवनी लोगों के जीवन के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस टेलीमेडिसिन सेवा ने अब तक 13 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सबसे अधिक तमिलनाडु में 3.74 लाख और उत्तर प्रदेश में 3.47 लाख लोगों तक सुविधा पहुंची। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से 2020 में 5.79 करोड़ शुगर की जांच और 7.13 करोड़ हाई बीपी की जांच की गई है।

2025 तक पांचवी तो 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है लेकिन मौजूदा सुधारों और वृद्धि की अनुमानित दिशा के मुताबिक भारत 2025 में ब्रिटेन से तो 2027 में जर्मनी और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2021 में अर्थव्यवस्था 9 % और 2022 में 7 % की दर से बढ़ेगी।



अब डिजिटल कैलेंडर

भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप लॉन्च हो गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी की लॉन्चिंग केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की।

इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर लिंक
<https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar>
 आईओएस लिंक
<https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594>

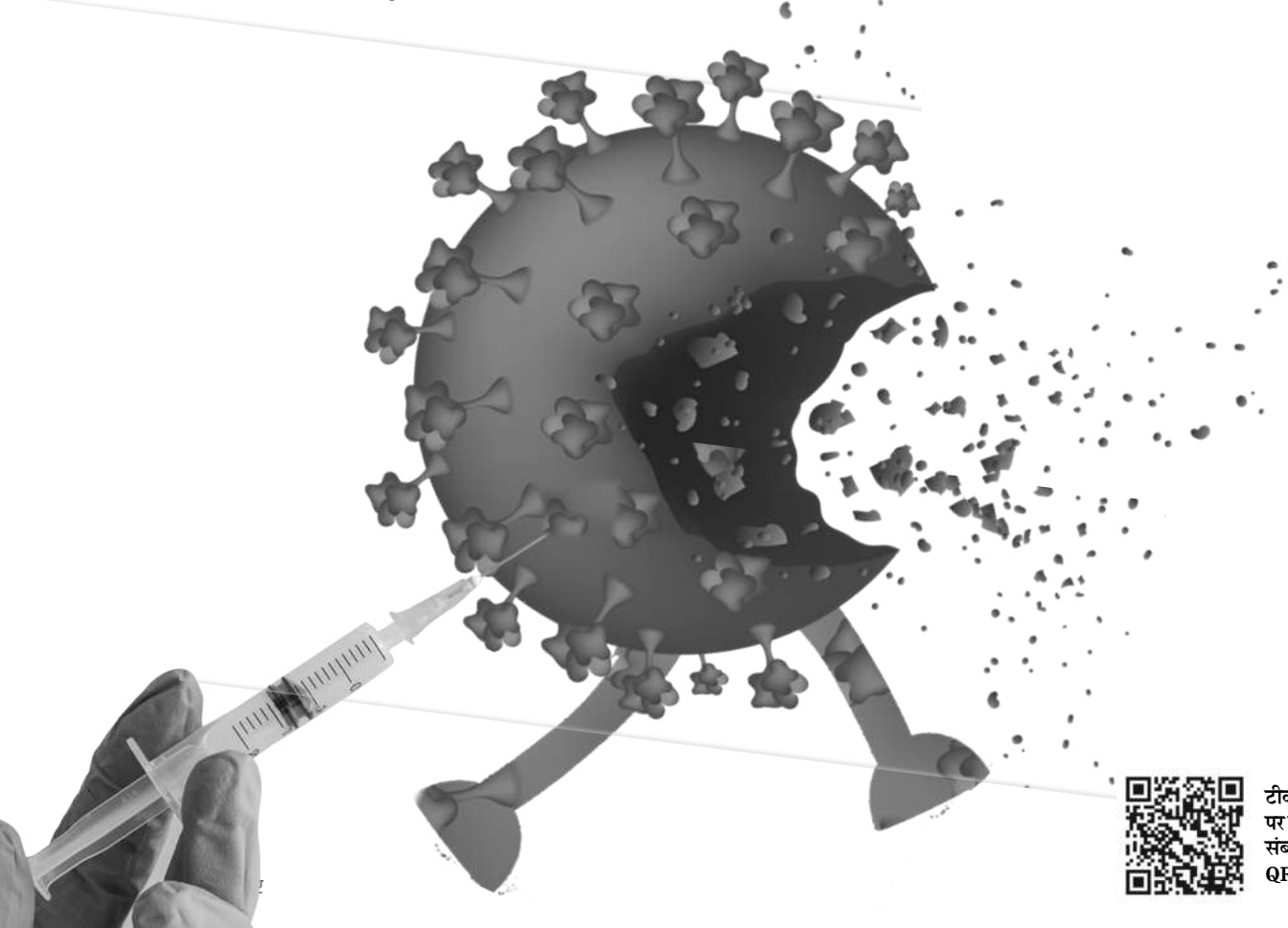
<https://goicalendar.gov.in/>

सर्वे भवन्तु सुखिनः | सर्वे सन्तु निरामयाः |

लगाने लगा उम्मीद का टीका



वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की विज्ञान, शोध और तकनीक को प्राथमिकता देते हुए समग्र दृष्टिकोण से लड़ी गई जंग अब एक निर्णायक क्षण में पहुंची। सीरम इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को ड्रग नियामक की मंजूरी और 16 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े महा-टीकाकरण अभियान से एक स्वस्थ और कोरोना मुक्त भारत की मुहिम को बल मिला तो महज 10 महीने में ईजाद हुई स्वदेशी वैक्सीन बनी आत्मनिर्भर भारत की अमिट पहचान



टीकाकरण की शुरुआत पर प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

अ

कसर इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलताओं की व्याख्या के लिए शाब्दिक उपमाएं कम पड़ जाती हैं। वह भी ऐसी आपदा से बाहर निकलने की सफलता जिसने दस महीने से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं पशु-पक्षी सबके जीवन को प्रभावित किया हो। इतने कम समय में एक ही देश में दो स्वदेशी वैक्सीन का साकार होना किसी चमत्कार से कम नहीं। सचमुच यह दुर्लभ है, लेकिन भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और 102 साल पहले आई स्पैनिश फ्लू के बारीक अध्ययन से बनाई गई कारगर रणनीति ने आपदा को इस कदर अवसर में बदला कि दुनिया दांतो तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। पहले लोगों के जीवन की रक्षा का संकल्प और फिर आर्थिक गति को रफ्तार देने की रणनीति के बाद वैक्सीन की उम्मीद को हकीकत में बदलते हुए भारत की कोरोना से जंग अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई है। विज्ञान, तकनीक और शोध को आधार बना कर अब भारत मानवता की सेवा के लिए स्वदेशी वैक्सीन के साथ दुनिया का नेतृत्व और जीवन की रक्षा करने को भी तैयार है।



ऐसे हुआ पूर्वाभ्यास ताकि सहज हो टीकाकरण

राष्ट्रव्यापी अभ्यास के तहत सभी 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 736 जिलों में 3 चरणों में कोरोना वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया।

वैक्सीन के लिए प्रशिक्षण के साथ ऐसे तैयार हुआ तंत्र

16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीन अभियान के लिए केंद्र ने सभी राज्यों के साथ 26 वर्चुअल मीटिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम किए।

2,360

मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए

61,000

हजार प्रोग्राम मैनेजर्स तैयार

02

लाख वैक्सीनेटर जो टीका लगाएंगे

3.7

लाख वैक्सीनेशन के लिए सहयोगी

एक टीम में 1 वैक्सीनेटर और 4 सहयोगी शामिल किए गए हैं।

- हर जिले ने तीन या ज्यादा स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, निजी अस्पताल और ग्रामीण या शहरी आउटरीच स्थान शामिल थे।
- जिला कलेक्टरों की देखरेख में यह पूर्वाभ्यास राज्य, जिला, ब्लॉक और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 रोल आउट के सभी पहलुओं से अवगत कराने के लिए संचालित किया गया।
- इसका उद्देश्य ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नियोजन, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग के लिए को-विन एप्लीकेशन के उपयोग और इस्तेमाल की मजबूती का आकलन करना था।

दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के इस अभियान के साथ ही इतिहास में भारत के लिए 16 जनवरी 2021 को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आपदा को अवसर में बदलने का उम्दा उदाहरण पेश करते हुए भारत ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सभी राज्यों के 3 हजार से अधिक टीकाकरण सेंटर पर इस अभियान को लांच किया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से कोवीशील्ड की 110 लाख खुराक 200 रु. प्रति खुराक पर खरीदी है।

जबकि भारत बायोटेक से कोवैक्सिन की 55 लाख खुराक खरीदी गई है। जिसकी औसत कीमत 206 रु. सरकार को पड़ेगी।

दुनिया की उम्मीद बना भारत

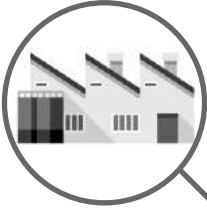
विश्व की 60 फीसदी वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। देश के पास हर साल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 65 करोड़ टीका लगाने का अनुभव है। ऐसे में दुनिया के सामने अनुभवी भारत सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। वैक्सीन ईजाद करने वाले देशों में भारत अग्रणी है। उसके ज्ञान-विज्ञान-कौशल की दुनिया भी मुरीद है। अगर दुनिया के 28 देशों में एडलमैन ट्रस्ट

कोल्ड चेन का मजबूत और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर



स्टेप-1

वैक्सीन निर्माता: 2
सीरम इंडिया की कोवीशील्ड
और भारत बायोटेक की
को-वैक्सीन



स्टेप-3

दूसरी श्रेणी के 35 स्टोर थे यानि कुल
39 स्टोर जिसे बढ़ाकर राज्यों में अब
60 जगहों को बड़े स्टोर में बदला
गया, हर राज्य में एक वैक्सीन स्टोर
अनिवार्य रूप से तैयार



बड़े राज्यों तैयार स्टोर

● उत्तर प्रदेश	9	● जम्मू-कश्मीर	2
● मध्य प्रदेश	4	● कर्नाटक	2
● गुजरात	4	● राजस्थान	2



स्टेप-2

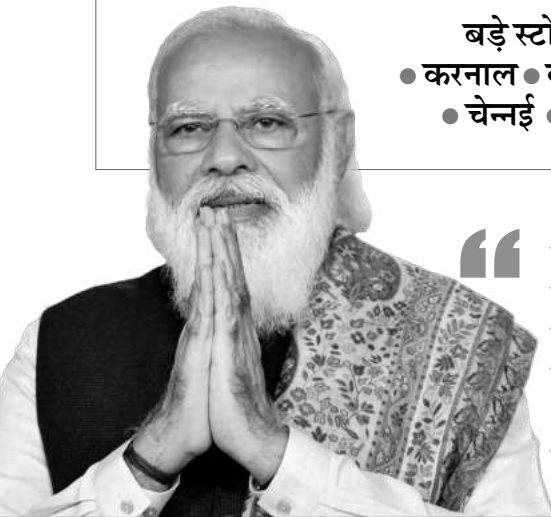
बड़े स्टोर- 4
● करनाल ● कोलकाता
● चेन्नई ● मुंबई



स्टेप-4

29,000

कोल्ड चेन केंद्र, वैक्सीन जहां
से सेंटर के लिए भेजने की
व्यवस्था



ये वैक्सीन भारत की स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई हैं। भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है, दूर-सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों और सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बैरोमीटर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो 80 फीसदी से ज्यादा भारतीयों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है जो दुनिया में सबसे अधिक है। जबकि ब्रिटेन में 66%, जर्मनी में 62, अमेरिका में 59 और रूस में 40 फीसदी लोगों को ही वहां की वैक्सीन पर भरोसा है। भारत के प्रति इस भरोसे की वजह वैज्ञानिकों का सामर्थ्य और संस्थान हैं।

विज्ञान और तकनीक बना आधार

विज्ञान और इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है। देश के शीर्ष नेतृत्व की यही सोच कोरोना की जंग में मूल आधार बनी। कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को शून्य से खड़ा करना हो या फिर लॉकडाउन में आम

लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए गरीब कल्याण पैकेज और अन्य आर्थिक सहायता पहुंचाना हो या फिर वैक्सीन ईजाद करने का सामर्थ्य दिखाना, केंद्र ने विज्ञान और तकनीक को ही सबसे बड़ा आधार बनाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के. विजयराघवन और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल की कमान वाली एक टास्क फोर्स गठित की। इनका काम वैज्ञानिक विश्लेषण करके सलाह देना था ताकि वैक्सीन के विकास को प्रोत्साहन मिले। अगस्त में प्रधानमंत्री ने एक और पहल करके नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (NEGVAC) का गठन

आप तक ऐसे पहुंचेगी कोविड वैक्सीन



स्टेप-5

14 जनवरी तक सभी केंद्रों पर उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन पहुंचाने का काम हुआ पूरा।



वैक्सीन सेंटर पर ये व्यवस्था की गई

- 240 वाक इन कूलर्स
- 70 वाक इन फ्रीजर्स
- 41 हजार डीप फ्रीजर
- 45 हजार आइस लाइन्ड रेफ्रीजरेटर्स
- 300 सोलर रेफ्रीजरेटर्स

स्टेप-7

वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन निगरानी के लिए को-विन (कोविड-19 वैक्सीन इंटेलेजेंस नेटवर्क) एप।



दवाई भी, कड़ाई भी

अब नया मंत्र हर वैक्सीन सेंटर पर जागरूकता अभियान वाले पोस्टर लगेंगे, मसलन- कौन से दस्तावेज जरूरी हैं वेरीफिकेशन के लिए, वैक्सीन के बाद क्या करना है आदि सावधानियों से जुड़ी सामग्री।

स्टेप-6

30

करोड़ प्राथमिक सूची वाले फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाने का काम पहले चरण में शुरू।



किया। जिसमें अंतर मंत्रालयी समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञों और अलग-अलग दिशाओं के पांच राज्यों को शामिल किया गया।

इस समूह ने वैक्सीन मंजूरी के पहले ही उसके भंडारण, कोल्ड चेन, खरीद की प्रक्रिया, वैक्सीन के प्रभाव को सुनिश्चित करना और किस तरह प्राथमिकता के आधार पर लोगों को पहुंचाई जाएगी, इसकी तैयारी कर ली। जुलाई के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेषज्ञों को वैक्सीन पहुंचाने के चार मंत्र देकर चौंका दिया था। उन्होंने ही इसे प्राथमिकता के तौर पर बांटने का सुझाव दिया था। पीएम केयर्स फंड और फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वैक्सीन के लिए भी सहायता दी गई। विज्ञान और तकनीक के साथ बेहतर समन्वय का ही नतीजा है कि चंद महीनों में ही न सिर्फ वैक्सीन तैयार है बल्कि पूरी निगरानी के साथ उसे अंतिम छोर तक पहुंचाने का ढांचा भी खड़ा हो चुका है।

वैक्सीन से पहले ही तैयार हुआ ढांचा

सामाजिक और जलवायु विविधता से भरे विशाल देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण कदम है। लेकिन कोरोना से

16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 18 जनवरी तक देश में 3 लाख 81 हजार 305 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

18 जनवरी तक देश में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं इसके मुकाबले मृत्युदर केवल 1.44% है।

जंग के हर स्तर की तैयारी का नतीजा है कि अंतिम छोर तक डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मानक गाइडलाइन भेजकर कोल्ड चेन की स्थिति की रिपोर्ट ली और फिर बिजली और बिना बिजली के संचालित होने



कोरोना वैक्सीन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, जिसे जानना है आपके लिए जरूरी

Q&A

क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी ? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्रथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा।

Q&A

यदि कोई पहले से कैंसर, शुगर, बीपी आदि जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वह कोरोना वैक्सीन ले सकता है ?

हां, इनमें से एक या अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है, जिन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की आवश्यकता है।

Q&A

क्या कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है ?

कोरोना के लिए वैक्सीन स्वैच्छिक है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है।

Q&A

क्या यह वैक्सीन सुरक्षित होगी क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया है ?

सुरक्षा और प्रभाव के डाटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है।

Q&A

क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है ?

पहले से संक्रमित होने के बावजूद वैक्सीन की पूरी खुराक लेना आवश्यक है क्योंकि यह एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में मदद करेगा।

Q&A

क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है ?

संक्रमित व्यक्तियों को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बात तक वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि इससे वैक्सीनेशन स्थल दूसरों को वायरस फैलाने का जोखिम बढ़ सकता है।

Q&A

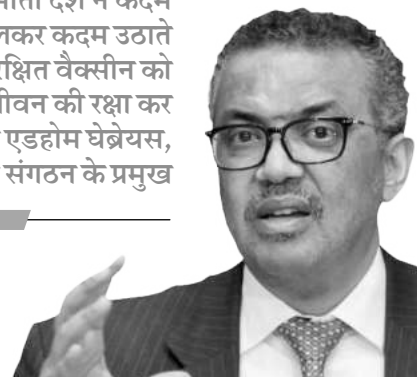
उपलब्ध कई वैक्सीन में से प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन कैसे चुनें ?

लाइसेंस देने से पहले ड्रग नियामक द्वारा वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभाव के डेटा की जांच की जाती है। इसलिए सभी लाइसेंस प्राप्त कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी सूची केवल एक प्रकार के वैक्सीन से पूरी होती है।



भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में लगातार निर्णायक कार्रवाई का प्रदर्शन किया है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश ने कदम उठाया है और अगर हम साथ मिलकर कदम उठाते हैं तो दुनिया भर में प्रभावी, सुरक्षित वैक्सीन को सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन की रक्षा कर सकते हैं। - टेड्रोस एडहोम गेब्रेयस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख

वाले कोल्ड चैन की मजबूती का आकलन किया। देश में पहले से 4 बड़े स्टोर थे और 35 दूसरी श्रेणी के थे। लेकिन केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर राज्य में एक बड़ा वैक्सीन स्टोर अनिवार्य रूप से होगा। इसके लिए सरकार ने 35 दूसरी श्रेणी वाले स्टोर को पहली श्रेणी के हिसाब से बनाया और कुल मिलाकर 60 ऐसे स्टोर तैयार किए। इसके अलावा टीकाकरण केंद्र तक भेजने के लिए जरूरत के हिसाब से वाक इन कूलर्स, डीप फ्रीजर, आइस लाइंड रेफ्रीजरेटर्स आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की। (देखें ग्राफिक) 14 जनवरी तक वैक्सीन भी निर्धारित केंद्रों तक पहुंचा दी गई थी।



Q&A

क्या भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन उतनी प्रभावी होगी, जितनी दूसरे देशों की वैक्सीन ?

हां, भारत में शुरु की गई कोरोना वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन। वैक्सीन परीक्षणों के विभिन्न चरणों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाती है।

Q&A

क्या भारत में कोरोना वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने और उन्हें आवश्यक तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है ?

भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन कार्यक्रमों को चलाता है जो 2.6 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की वैक्सीनेशन की जरूरतों को पूरा करता है। देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मजबूत किया गया है।

Q&A

क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है ?

नहीं, वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही वैक्सीन सेंटर और समय की जानकारी साझा की जाएगी।

Q&A

यदि कोई व्यक्ति सेंटर पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा ?

फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है।

Q&A

मैं वैक्सीनेशन के लिए योग्य हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा ?

पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जाएगा। पर्याप्त स्वास्थ्य जांच के बाद रिपोर्ट सामान्य रहने पर व्यक्ति को वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जाएगा।

Q&A

क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी ?

हां, कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर, लाभार्थी को मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। वैक्सीन देने के बाद क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र भी मोबाइल पर भेजा जाएगा।

Q&A

खुराक लेने के बाद एंडीबॉडी कब विकसित होगी ?

कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद आम तौर पर एंडीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है।

Q&A

क्या कोई निवारक उपाय और सावधानियां हैं जिसे सेंटर पर पालन करने की आवश्यकता होगी ?

वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीन सेंटर पर ही आराम करना होगा। यदि बेचैनी महसूस होती है तो स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करें। बाद में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें- जैसे मास्क पहनना, हाथ की सफाई और दो गज की दूरी।

Q&A

लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?

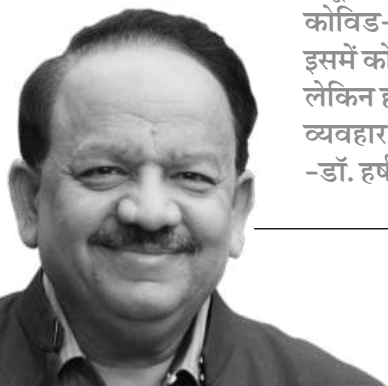
फोटो के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आदि।



वैक्सीनेशन के लिए हमारी पूरे देश में संपूर्ण तैयारी है। अगर मैं कहूँ कि यह कोविड-19 के अंत की शुरुआत है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी अपील है कि लोग कोविड व्यवहार का पालन लगातार करते रहें।
-डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

हम सुरक्षित, देश सुरक्षित

यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ इम्युनिटी प्रदान करेगा और कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करेगा। यह इंजेक्टबल वैक्सीन है। दुनिया के अन्य वैक्सीन के मुकाबले भारत की वैक्सीन किफायती और कारगर भी है। टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को पहले पंजीकरण कराना होगा, उसके बिना वैक्सीन नहीं मिलेगी। पंजीकरण के बाद मोबाइल पर एसएमएस आएगा। फिर टीकाकरण के दिन, समय और स्थान की जानकारी देने का एसएमएस आएगा। तीसरा एसएमएस टीका



किफायती और कारगर होगी स्वदेशी वैक्सीन

उत्पादक	कीमत	तापमान
कोवीशील्ड (भारत)	200	2-8 डिग्री
कोवैक्सिन (भारत)	206	2-8 डिग्री
फाइजर (कई देश में प्रयोग हो रहा)	1431	-70 डिग्री
मॉडर्ना	2700	2-8 डिग्री
साइनोफार्म (चीन)	5650	2-8 डिग्री
साइनोवेक बायोटेक (चीन)	1027	2-8 डिग्री
नोवावैक्स	1114	2-8 डिग्री
स्पूतनिक-V (रूस के गमालिया सेंटर की)	734 *	2-8 डिग्री
जॉनसन एंड जॉनसन	734	2-8 डिग्री

कीमत- रुपये में, * जब भारत में इसका उत्पादन होगा तब यहां की कीमत अलग

कोरोना से जंग में भारत ने किया दुनिया का नेतृत्व सही समय पर सधे कदम

- जब पीएम मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया, तो उस समय भारत में महज 500 के करीब मामले थे।
- भारत ने लॉकडाउन लगाने में अगर और इंतजार या देरी की होती तो यहां के हालात यूरोप और अमेरिका से भी बदतर हुए होते।
- कोरोना के नये मामले एक सप्ताह में 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो गए और दोगुने होने का समय सिर्फ तीन दिन से अधिक था।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय लॉकडाउन का फैसला लिया, तब तक किसी अन्य देश ने नहीं लिया था।
- यदि लॉकडाउन का रास्ता चुनने में देरी की होती तो कोई मदद नहीं मिलती। क्योंकि सभी अस्पताल भरे हुए थे और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था।
- सरकार ने लॉकडाउन के चुनौतीपूर्ण समय में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 15,362 हेल्थ फैसिलिटीज, लगभग 15.40 लाख आइसोलेशन बेड, 2.70 लाख आक्सीजन सपोर्टेड बेड और 78,000 आईसीयू बेड तैयार किए गए।
- देश के सरकारी अस्पतालों को 32,400 वेंटिलेटर डिलीवर किए। अगर इस बात की तुलना पिछले 70 सालों से की जाए तो, इन सरकारी अस्पतालों में इससे पहले केवल 12,000 वेंटिलेटर ही मौजूद थे।
- इस दौरान ही राज्य सरकारों को 3.70 करोड़ एन-95 मास्क और 1.60 करोड़ पीपीई किट प्रदान की गईं।

चार अन्य वैक्सीन जिनका भारत में हो रहा रिसर्च और विकास...

- जाइडस कैडिला: इसका फेज-2 का ट्रायल पूरा हो चुका और फेज-3 ट्रायल शुरू हो चुका है।
- स्पूतनिक-v: गमालिया इंस्टीट्यूट, रूस के द्वारा विकसित हुई है। लेकिन भारत में डॉ. रेड्डीज लैब के सहयोग के साथ ट्रायल का फेज-2 पूरा और फेज-3 जारी है। इसका उत्पादन भारत में ही होगा।
- बायोलॉजिकल ईवांस: हैदराबाद की कंपनी है, जिसका फेज-1 का ट्रायल शुरू हो चुका है और फेज-2 का ट्रायल मार्च 2021 में शुरू होगा।
- जिनोवा: पुणे की कंपनी है और यह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन बना रही है। इसका फेज-1 ट्रायल चल रहा है और दूसरा चरण मई 2021 में होगा।

लगाए जाने और टीकाकरण की अगली तारीख की जानकारी देने के लिए किया जाएगा। दूसरी डोज लगाए जाने के बाद चौथा एएसएमएस आएगा जिसमें डिजिटल प्रमाणपत्र का लिंक भी होगा। पूर्ण वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हाथ धोने, दो गज की दूरी और मास्क लगाना होगा।

निश्चित तौर से भारत ने कोरोना पर पांच प्रमुख सिद्धांतों के साथ प्रहार किया है। इनमें जन भागीदारी, चुनावों में बूथ स्तर के काम और सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़े, वैज्ञानिक और नियामक मानदंडों के पालन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अभियान को चलाना शामिल है। इन पांच सिद्धांतों का ही नतीजा है कि भारत ने टीकाकरण शुरू कर दिया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार देश को संबोधित कर रहे होंगे, भारत सिर्फ आजादी की वर्षगांठ नहीं मना रहा होगा, बल्कि कोरोना से मुक्ति की दिशा में बढ़ते कदम और नई सुबह भी देख रहा होगा। ●

“ साधारण तरीके से वैक्सीन बनाने में आठ से दस साल लगते हैं, लेकिन इसका ईजाद करने में भारत अग्रणी श्रेणी में रहा ”

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। टीका बनने, प्रोटोकॉल व टीकाकरण की प्राथमिकता तय करने के बाद चुनाव में बूथ प्रबंधन की तरह ही टीकाकरण का प्रबंधन किया जा रहा है। वैक्सीन के सफर पर राष्ट्रीय उच्च स्तरीय समूह (नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19) के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल से न्यू इंडिया समाचार के सलाहकार संपादक संतोष कुमार ने बातचीत की। पेश है उसके अंश:

Q इतनी बड़ी आपदा से निपटने से लेकर वैक्सीन तक पहुंचने को लेकर सरकार की प्रारंभिक सोच क्या थी?

A भारत की प्रतिक्रिया इस महामारी में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी रही है। अप्रैल के महीने में ही एक टास्क फोर्स गठित करके उसे वैक्सीन के लिए विज्ञान व तकनीकी समाधान खोजने व सुविधाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और वैक्सीन उद्योग में जुड़े लोगों को साथ लेकर प्रोत्साहित किया गया। जब वैक्सीन की संभावनाएं बढ़ीं तो सरकार की तरफ से संसाधन और फंड भी उपलब्ध कराए गए। शुरु से लक्ष्य यही था कि देश में वैक्सीन ईजाद करने के साथ उत्पादन करना भी है। आज हम सफल हुए हैं और अन्य चार वैक्सीन ट्रायल के चरण में हैं। आगे नए वैक्सीन भी आएंगे और जो तैयार हैं उनका उत्पादन बढ़ता जाएगा।

Q वैक्सीन के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से कोल्ड चेन की तैयारी कैसी हुई?

A देखिए, भारत के पास गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का एक लंबा अनुभव है। हर साल 65 करोड़ से भी ज्यादा टीके 90 लाख से अधिक सत्र में लगाए जाते हैं। काफी हद तक कोल्ड चेन की व्यवस्था थी जिसे मौजूदा जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया। टीकाकरण में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षित किया। आईटी प्लेटफॉर्म की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन प्रबंधन की सूक्ष्म स्तर की योजना बनाई गई। जो लाभार्थी हैं उन्हें चिन्हित करना, टीके की जगह और समय बताने का काम और लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए फॉलोअप भी इसी से होगा।

Q लेकिन कोल्ड चेन की संख्या बढ़ाने के लिए और क्या-क्या किया गया है?

A अगर कोल्ड चेन के विस्तार की बात करें तो हमारे पास चार बड़े और



“

हमारे दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास हजारों लोगों पर किया गया अनुभव और डाटा है। प्रतिरक्षण ताकत पैदा करने को लेकर कोई संदेह नहीं है। ये बहुत रोबस्ट (मजबूत) हैं। हमें अथोराइजेशन से मौका मिला है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। अभी जिन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जब उनके परिणाम आएंगे तब और भी हमें समझ आएगा।



वैक्सीन का सफर चुनौतीपूर्ण रहा लेकिन भारत और हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य को लेकर कभी कोई संदेह या दो राय नहीं था। जिसका नतीजा सामने है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने टीम इंडिया की तरह काम किया।



इतनी बड़ी आपदा थी, लेकिन नौ-दस महीने में स्वदेशी वैक्सीन आ गई ?

यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि साधारण तरीके से वैक्सीन बनाने में आठ से दस साल लगते हैं। लेकिन देशों में होड़ लगी और हमारा देश बिल्कुल अग्रणी श्रेणी में है। दो वैक्सीन को ऑथोराइजेशन मिली तो चार मानवीय परीक्षण के फेज में हैं। कुछ बिल्कुल एडवांस डीएनए और आरएनए तकनीक पर आधारित है जिसे तेज गति से बनाया।

दूसरी श्रेणी के मेडिकल डिपो करीब 35 को मिलाकर कुल 39 थे। अब दूसरी श्रेणी वालों को भी पहले वाले की तरह बनाया गया है। अब इसमें कुछ नई व्यवस्था के साथ ऐसे कोल्ड स्टोर की संख्या को बढ़ाकर 60 तक पहुंचाया गया है। यानी अब ये पहले वाली श्रेणी के ही 60 से अधिक हो गए हैं। इसके बाद 29 हजार से भी ज्यादा कोल्ड चेन प्वाइंट्स होंगे जिसका इस्तेमाल टीकाकरण में किया जाएगा।

Q सबको टीका मिले यह बहुत बड़ी चुनौती है। उससे सरकार कैसे निपटेगी ?

A इतने बड़े स्तर का टीकाकरण ही अपने आप में चुनौती है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का कार्यक्रम पूरा करेंगे। लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी। वैक्सीन की उपलब्धता अभी कम है। पहले 30 करोड़ प्राथमिक सूची वालों को लगाएंगे और फिर उसके आगे भी टीकाकरण करेंगे।

Q अगला चरण कब शुरू किए जाने की क्या संभावना है ?

A अभी 30 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने में सात-आठ महीने लगेंगे। बाकी वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ टीकाकरण का अभियान भी तेज गति से बढ़ सकता है।

Q केंद्र सरकार ने राज्यों को साथ लेकर संघीय ढांचे का बड़ा उदाहरण पेश किया, क्या कभी कोई मतभेद भी रहा ?

A इसमें मतभेद की बात ही नहीं है। कोरोना से निपटने की कार्यपद्धति में आम राय की कोई कमी नहीं रही है। हर बार आम राय यही बनी कि वैक्सीन को लेकर आगे बढ़ा जाए। यह सारा काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्रियों ने बिल्कुल एक टीम इंडिया की तरह काम किया है और आगे भी करेंगे।

Q अनुमान के मुताबिक, टीका पर कुल कितना खर्च आएगा ?

अभी इसके खर्च पर बात करना शायद उचित नहीं होगा। अभी थोड़ी सी

A वैक्सीन खरीदी गई है, आगे ज्यादा खरीदी जाएगी। खर्च सिर्फ वैक्सीन में नहीं होता है। वैक्सीन के प्रचार और जागरूकता अभियान, सीरिज सहित अन्य खर्च भी होता है। जब काम इतना बड़ा होता है तो और खर्च भी होते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसाधनों में कोई कमी नहीं होगी।

Q कोरोना से निपटने से लेकर वैक्सीन ईजाद करने तक, भारत की लड़ाई की डब्ल्यूएचओ और दुनिया के देशों ने भी सराहना की। इसे एक विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं ?

A कोरोना की लड़ाई में भारत की उपलब्धि से बेहद संतुष्टि है। इतने बड़े और सघन आबादी वाले देश व इलाके में हमने किस तरह लड़ाई लड़ी, उसे दुनिया भी देख रही है। शुरुआती दौर में ही कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड व बिस्तर तैयार किए। हम पहले पीपीई किट व वेंटिलेटर बिल्कुल नहीं बनाते थे, अब उसके निर्यातक हैं। टेस्टिंग में हम जीरो से शुरू होकर आज हर दिन 15 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता तक पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में तैयारी से संक्रमण की रफ्तार घटी और मृत्युदर 1.4 फीसदी तक रखने में मदद मिली। इतनी नीचे मृत्युदर बहुत कम देशों में है। अगर हम बाकी देशों को देखें तो वहां दूसरी लहर भी आई और काफी संक्रमण फैला। हम बचे हुए हैं। अब वैक्सीन आ गई है तो महामारी को नियंत्रण में करने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी।

Q वैक्सीन को लेकर प्राथमिक समूहों का चयन या विशेषज्ञ के तौर पर आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

A मेरा कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों से टीका करण अभियान इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इनमें संक्रमण की आशंका अधिक रहती है। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की जानें बचाई हैं। आगे भी ऐसा होता है तो सुरक्षित और प्रेरित स्वास्थ्य टीम चाहिए। उसके बाद अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों की बारी है। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आइटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव के समय बूथ स्तर पर योजना बनाई जाती है और निर्धारित संख्या में लोग बूथ में आते हैं और वोट देकर जाते हैं, उसी तरह टीकाकरण में भी होगा।

नई तकनीक से होगा सबको आवास का सपना साकार

केंद्र सरकार की सोच सबको 2022 तक सिर्फ अपना मकान देना ही नहीं, बल्कि उसकी सोच गरीब और मध्यम वर्ग को ऐसा किफायती, टिकाऊ और आरामदायक मकान देने की है जो लंबे समय तक चलने वाला हो। इसी सोच के तहत नए साल में सरकार ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत विश्वस्तरीय तकनीक को इस क्षेत्र में जोड़ा है ताकि कम समय में, बेहतर तकनीक से तैयार मजबूत मकान लोगों को मिल सके



शहर में रहने वाले गरीब हो या मध्यम वर्ग, हर किसी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती है। सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है। मुश्किल के समय एक गारंटी और सुकून रहता है कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना घर तो है। 'हाउसिंग फॉर ऑल' के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के प्रयास देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस काम को गति देने के लिए नई तकनीक को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जोड़ दिया है, जिसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस परियोजना के तहत पारंपरिक तौर पर ईट और कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से यानी 12 महीनों के भीतर गृह प्रवेश की स्थिति के लिए मकान को तैयार करना है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) इंडिया का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को न्योता दिया। जिसमें दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने चैलेंज में हिस्सा लिया। इसमें से चुनी गई 6 तकनीकों के साथ अगले चरण में अब अलग-अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। अब योजना के तहत मकान आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रक्रिया से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों के लिए किफायती, लचीला, आरामदायक घर तैयार होंगे। फिलहाल ये तकनीक एक शहर में इस्तेमाल हो रही है लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है।

‘नवरीति’ से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) इंडिया के तहत शहरी विकास व आवास मंत्रालय की ओर से बिल्डिंग मैटिरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (बीएमटीपीसी) और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से नवरीति (NAVARITI) यानी न्यू, अफोर्डेबल, वैलिडेटेड, रिसर्च इनोवेशन, टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग नाम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। कोर्स की पाठन सामग्री का पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया। इसमें जीएचटीसी इंडिया के तहत चयनित 54 नवीन तकनीकों का भी विवरण है। यह कोर्स आर्किटेक्चर, इंजीनियरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल और आवास क्षेत्र के अन्य हित धारकों को विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली नवीनतम, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं-प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इससे देश में नवीनतम तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनका उपयोग आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को नई गति देगा।



हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी, हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए। जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों न हो। सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे न हो बल्कि स्टार्ट अप की तरह चुस्त भी और दुरुस्त भी होने चाहिए।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

ये लाइट हाउस परियोजनाएं आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रक्रियाओं से बनी होंगी, जो इसे गरीबों के लिए अधिक किफायती और आरामदायक बनाती हैं। कैसे बनेंगी छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजनाएं:

 <p>इंदौर में इस परियोजना में ईट और मोर्टार की दीवारें नहीं होंगी, इसके बजाए पूर्व निर्मित सैंडविच प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।</p>	 <p>राजकोट में लाइट हाउसेज को आपदाओं से निपटने में सक्षम फ्रेंच तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा।</p>	 <p>चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजी प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम के उपयोग से घर सस्ता व निर्माण तेजी से होगा।</p>
 <p>रांची में जर्मनी के 3डी कंस्ट्रक्शन सिस्टम का उपयोग होगा। पूरा स्ट्रक्चर अलग से बनेगा और लेगो ब्लॉक खिलौने की तरह से जोड़ा जाएगा।</p>	 <p>अगरतला में न्यूजीलैंड की तकनीक का उपयोग। स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे, जो भूकंप का सामना करने में सक्षम।</p>	 <p>लखनऊ में कनाडा की तकनीक का उपयोग। प्लास्टर-पेंट जरूरी नहीं। पहले से तैयार दीवारों का उपयोग किया जाएगा।</p>

- हर स्थान पर 12 महीनों में 1 हजार घर बनाए जाएंगे जो इन्क्यूबेशन सेंटर की तरह काम करेंगे, जिसके माध्यम से प्लानर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और छात्र नई तकनीक सीखने, प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- आशा इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से 21वीं सदी के घरों के निर्माण के लिए नई और सस्ती तकनीक भारत में ही विकसित की जाएगी।
- रियल इस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निर्णय ले रही है, इसमें सस्ते मकानों पर टैक्स को 8 फीसदी से घटाकर 1% और जीएसटी भी 12% से घटाकर 5 % कर दिया गया है।
- भारत की रैंकिंग बेहतर: बीते वर्षों में किए गए सुधारों से निर्माण परमिट में भारत की रैंकिंग 185 से घटाकर 27 हो गई है। निर्माण संबंधी परमिट के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार 2 हजार से अधिक शहरों में हुआ है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई(यू)) के तहत अब तक करीब 1.10 करोड़ घर मंजूर किए गए हैं।

गणतंत्र की गौरव गाथा





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए।



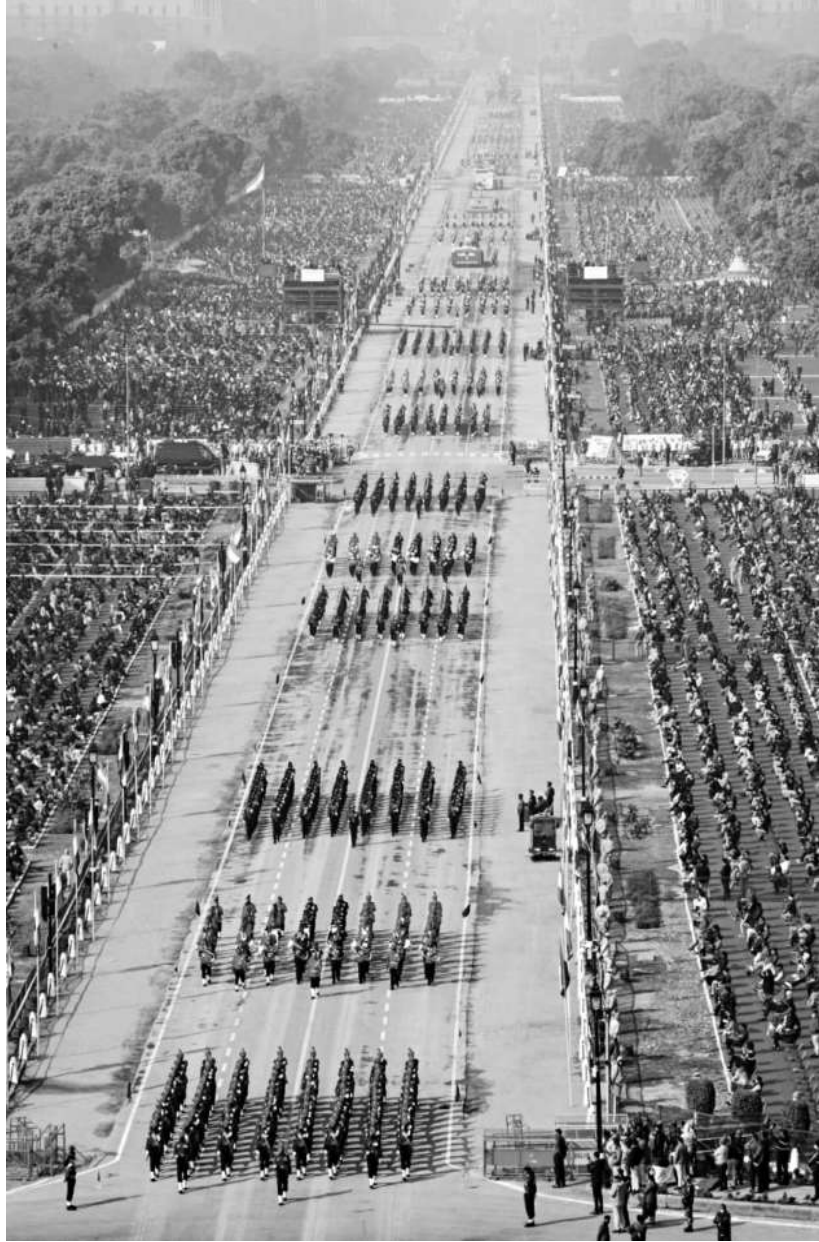
72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण के लिए मंच पर जाते हुए।



गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें



राफेल (सबसे आगे): पहली बार परेड में हिस्सा लिया।



जीवन पर्यन्त कर्तव्य ...
राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल का दस्ता।



राजपथ पर दुनिया ने
देखा भारत का शौर्य।



ताकत वतन की...
राजपथ पर एनसीसी छात्राओं का मार्च।



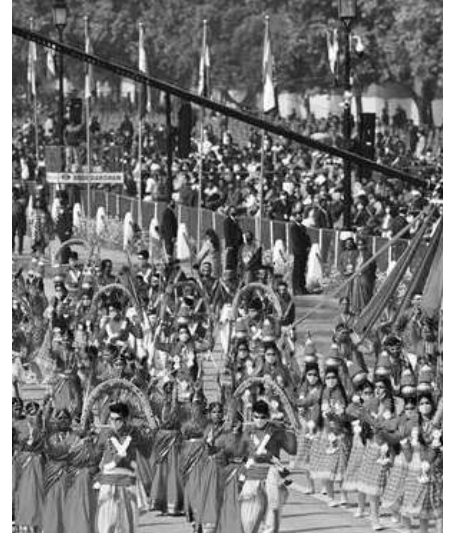
पहली बार महिला पायलट
फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ
वायुसेना की तरफ से परेड में
हिस्सा लेने वाली पहली महिला।



सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा...
राजपथ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो (एनएसजी)

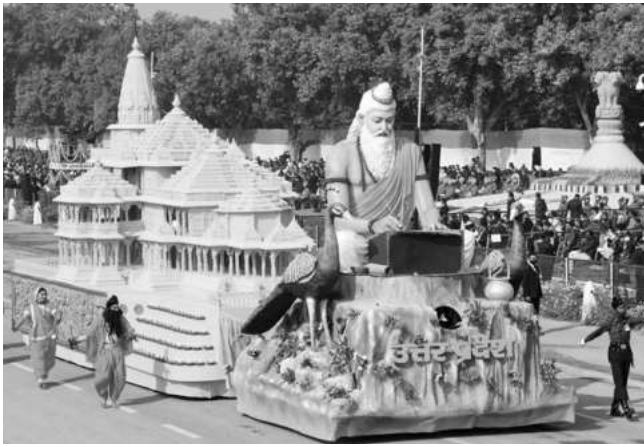


वोकल फॉर लोकल की झलक...
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी ने दिया संदेश।



अनेकता में एकता...

स्कूली छात्रों ने राजपथ पर दिखाई भारतीय संस्कृति की झलक।



पहली बार राम मंदिर ...
राम मंदिर पर उत्तर प्रदेश की झांकी



कोरोना से जंग...

कोविड वैक्सीन पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी।



नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी।



केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की झांकी में दिखे सरदार पटेल।



राजपथ पर पहली बार दिखी लद्दाख की झांकी में दिखी वहां की संस्कृति।



1 देश

व्यवस्था

सुविधा

एकीकृत भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ते कदम

सामान्य लोगों का जनजीवन हो या फिर उनके जीवन को सुविधा प्रदान करने वाले साधन, महत्वाकांक्षी और दूरदृष्टा सोच के साथ केंद्र सरकार भारत को एकसूत्र में बांधने की दिशा में काम कर रही है। इसी सोच को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक गैस ग्रिड की दिशा में कोच्चि-मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। बीते दिसंबर महीने में भी दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली बिना ड्राइवर वाली ट्रेन के परिचालन के साथ एक देश-एक कार्ड (एनसीएमसी) सेवा का शुभारंभ किया गया तो जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत की शुरुआत भी हुई...

ए

क देश-एक राशन कार्ड, एक देश-एक परीक्षा, एक देश-एक टैक्स के बाद अब केंद्र सरकार ने एक देश-एक गैस ग्रिड और एक देश-एक कार्ड (एनसीएमसी) सेवा की शुरुआत की है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 किमी लंबी कोच्चि-मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण एक देश-एक गैस ग्रिड योजना का हिस्सा है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल आम बजट में की थी। इसके जरिए केंद्र सरकार पूरे देश में गैस पर एक समान टैरिफ लागू करना चाहती है। परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र को लेकर अपनी सरकार का खाका देश के समक्ष रखते हुये कहा कि ऊर्जा उपभोग में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को दोगुने से अधिक किया जाएगा। पूरे देश को एक गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों और उद्योगों को किफायती ईंधन मुहैया कराया जा सके।



इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के अहम बिंदु...

- सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन, जल, डिजिटल और गैस संपर्क पर अभूतपूर्व काम कर रही है। इस पाइपलाइन को तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।
- एक तरफ पांच-छह साल में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना कर करीब 32 हजार किलोमीटर का बनाया जा रहा है, दूसरी ओर गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्र पर काम चल रहा है।
- पिछले छह साल में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से बढ़कर 1,500 हो गयी है। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 2014 तक 25 लाख घरों के पास रसोई गैस के लिये पाइप (प्राकृतिक गैस) कनेक्शन थे। अब ये बढ़कर 72 लाख घरों तक पहुंच गये हैं।
- इस पाइपलाइन से केरल और कर्नाटक में 700 सीएनजी स्टेशन लगाने तथा 21 लाख घरों में पाइप से एलएनजी पहुंचाने में मदद मिलेगी।

हम स्वच्छ, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। छह साल में एलपीजी के 14 करोड़ कनेक्शन दिये गये हैं। यह इससे पहले के छह दशक में दिये गये कनेक्शनों के बराबर है। इनमें से आठ करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को दिये गये हैं। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



देश गैस ग्रिड

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक घर में एलपीजी गैस उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही वाहनों के ईंधन के लिए सीएनजी गैस उपलब्ध कराना भी योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के तहत, वे सभी क्षेत्र जहां घरेलू गैस उपलब्ध नहीं है, लाभांशित होंगे।
- पाइपलाइन से घरेलू गैस की आपूर्ति होगी ही, वाहनों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी की भी आपूर्ति होगी। एक देश-एक गैस ग्रिड' योजना से स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों की सेहत अच्छी होगी और बीमारियों पर खर्च में कमी आएगी। शहरों में गैस आधारित व्यवस्था का विकास होगा जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- एक देश, एक गैस ग्रिड' के कारण कम खर्च में फर्टिलाइजर बन सकेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी। फर्टिलाइजर के साथ ही बिजली और केमिकल जैसे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विदेशी मुद्रा का खर्च भी कम हो जाएगा।

1 राष्ट्र का सपना काड साकार

28 दिसंबर को दिल्ली की मैजेंटा लाइन पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत ड्राइवरलेस मेट्रो वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक देश-एक मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत की।

“शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।”

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के अहम बिंदु:

- भविष्य की जरूरतों के लिए देश को तैयार करना ये शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 2014 में देश में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो की सेवा उपलब्ध है। वर्ष 2025 तक 25 से अधिक शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा।
- 2014 में सिर्फ 248 किमी मेट्रो लाइन संचालित, आज यह लगभग तीन गुनी यानी 700 किमी से अधिक है। वर्ष 2025 तक इसका विस्तार 1700 किमी तक करने का प्रयास जारी है।
- दिल्ली और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिससे यात्रा का समय एक घंटे से भी कम हो जाएगा।

एक देश-एक सुविधा की दिशा में बढ़ते कदम



● एक देश, एक राशन कार्ड से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशनकार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। इसी तरह नए कृषि सुधारों और ई-नाम से एक देश, एक बाजार की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है।



● एक देश, एक गैस ग्रिड से उन हिस्सों की निर्बाध गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है, जहां गैस आधारित जीवन पहले सपना हुआ करता था। पीएमजय-आयुष्मान भारत योजना में एक देश, एक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम से देश के करोड़ों लोग देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं



● एक देश, एक फास्टैग से देश के हाइवे पर निर्बाध ट्रैफिक संभव हो पाया है। एक देश, एक टैक्स यानी जीएसटी से देशभर में टैक्स का जाल समाप्त हुआ है। एक देश, एक पावर ग्रिड से देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है



● एक देश-एक परीक्षा के माध्यम से अब अलग-अलग सरकारी नौकरी के लिए अलग-अलग परीक्षा के जाल से मुक्ति मिली है।

जम्मू-कश्मीर में 21 लाख परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज



भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना पीएमजय-आयुष्मान की तर्ज पर अब जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना की शुरु की गई है। योजना से 21 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश के करीब 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है।

“मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बधाई देता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ‘इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत’ का कथन हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जम्मू-कश्मीर का विकास हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।”

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



(नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड)

- पूरे देश में मेट्रो, बस, कैब, मोनोरेल और सभी अर्बन रेलवे में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) यानी एक ही कार्ड से सभी तरह के परिवहन साधनों में यात्रा की सुविधा।
- वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों द्वारा सभी नए डेबिट कार्ड को एनसीएमसी के उपयोग के अनुरूप बनाना अनिवार्य किया।
- स्वदेशी एएफसी गेट्स के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास में जुटा है।
- दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (23किमी) इस वन नेशन वन कार्ड की सुविधा को लागू करने वाला पहला मेट्रो नेटवर्क बना।
- 1.1 करोड़ से अधिक डेबिट रूपे कार्ड धारक हाल ही में जारी किए गए कार्ड का उपयोग एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर कर सकेंगे।
- पिछले एक साल से अधिक समय में जारी एसबीआई, इलाहाबाद, केनरा, यूबीआई, यूको, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी समेत 23 बैंकों के रूपे कार्ड काम करेंगे।
- दिल्ली मेट्रो का लगभग 400 किमी का हिस्सा अगस्त 2022 तक पूरी तरह से एनसीएमसी के अनुकूल बनाए जाने की योजना है।
- बड़ी वॉटर बॉडीज वाले शहरों के लिए अब वॉटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है, जो जल मेट्रो द्वीपों के पास लोगों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- आज 4 बड़ी कंपनियां भारत में मेट्रो कोचों का निर्माण कर रही हैं और दर्जनों अन्य मेट्रो घटकों के निर्माण में जुटी हैं।
- हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50 फीसदी ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है।
- आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 मेगावाट तक ले जाया जाएगा। ●

युवा उत्साह और आकांक्षाओं की उड़ान से लैस होगा नया भारत

स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करते हुए केंद्र सरकार देश के युवाओं के सहारे नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बढ़ा रही है कदम ...



मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी में है। वे शेरों की तरह सारी समस्या का समाधान करेंगे।" स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार एक ऐसे नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ चुकी है जहां युवा खुलकर अपनी प्रतिभा, सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके। इसके लिए अनुकूल माहौल और ढांचा खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है, "न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है- उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा।" संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'हम देश में एक इको सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अभाव में युवा अक्सर बाध्य होकर विदेश की ओर देखते हैं।' प्रधानमंत्री ने विवेकानंद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मंत्र, 'अपने-आप पर भरोसा करो' और लीडरशिप के मंत्र- 'सब पर भरोसा करो', से युवाओं को उस लाइन पर चलकर अध्याय गढ़ने का आह्वान किया। फिर कहा, स्वामी

विवेकानंद कहते थे, 'पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता। लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता।' इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया था।

देश में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 12-16 जनवरी तक हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 दिसंबर 2017 के मन की बात में दिए गए विचार के बाद से इस युवा महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन और उन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टता पर विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करना है। इस साल के महोत्सव की थीम- 'युवा-उत्साह नए भारत' की थी। जिसका मतलब है कि युवा नए भारत के उत्सव को जीवंत रखते हैं। इसका मकसद राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, साहस और हिम्मत की भावना को प्रोत्साहन देकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है।

युवा भारत-सशक्त भारत

स्वयं प्लेटफॉर्म

16 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने 3605 पाठ्यक्रम पूरे किए।

ज्ञान योजना

58 देशों के 800 प्रोफेसर, 2101 कोर्स का संचालन।

डिजिटल लाइब्रेरी

3 लाख लेखकों के 10 मिलियन आइटम मुफ्त

- इम्प्रिंट इंडिया-1 और 2 के तहत 2612 प्रस्ताव प्राप्त हुए और 142 परियोजनाओं पर क्रियान्वयन जारी है।
- स्किल इंडिया के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।
- पूरे देश में 580 से ज्यादा जॉब रोल के लिए 22,500 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- करीब 5 हजार आईटीआई स्थापित और 2015 के मुकाबले 85.5 फीसदी क्षमता बढ़ाकर 34.63 लाख की गई।
- स्ट्राइव के तहत नई पहल और बड़ी उपलब्धि: 244 आईटीआई ने प्रदर्शन आधारित अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 21वीं सदी के कौशल से जुड़ी महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) हासिल करने को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू।
- आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 566 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई।
- 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 ट्रिपल आईटी, 1 एनआईटी, 103 केंद्रीय विद्यालय व 62 नवोदय विद्यालयों का कार्य प्रारंभ।
- प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत प्रतिभाशाली युवाओं को 5 वर्षों के लिए 70-80 हजार मासिक छात्रवृत्ति और पीएचडी व शोध के लिए 2 लाख रु. का वार्षिक शोध अनुदान।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी प्रोफेशनल परीक्षाएं आयोजित करेगी।
- उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान, 20 संस्थान प्रतिष्ठित संस्थान घोषित।
- सरकार ने अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रु. की मंजूरी दी।
- ओबीसी की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय की पात्रता 44,500 से बढ़ाकर 2.5 लाख व एससी के लिए भी 2.5 लाख की गई।
- खेल शिक्षण व प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला संस्थान होगा।
- गुजरात के गांधीनगर में पैरा एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला पहला प्रशिक्षण केंद्र।
- आस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन से 66 पदक जीते, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 साल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रु की सहायता।
- जनवरी 2018 में शुरू पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 3,507 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 3 साल में 1756 करोड़ रु खर्च।
- एक हजार खेलो इंडिया केंद्र स्थापना की घोषणा, 24 खेलो इंडिया स्टेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी और 8 लांच किया गया।
- रोजगार सृजन की तिहरी कार्यनीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र और पर्सनल सेक्टर को नया जीवन देने से नए अवसर सामने आए।
- बजट 2019-20 में मुद्रा योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक महिला को 1 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया।

स्किल मैपिंग पर विशेष जोर

15 देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र में जॉब रोल की मैपिंग हेतु विभिन्न कदम उठाए।



41,838

रोजगार के अवसरों को बढ़ावा

स्टार्ट-अप को मान्यता और उसे 7 साल के ब्लॉक में लगातार 3 वर्षों तक टैक्स में राहत।

स्टार्ट अप को कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले प्रमोटरों को ईएसओपी जारी करने की अनुमति।

शिक्षा व्यवस्था में सशक्तीकरण

यूजीसी ने शीर्ष 60 विश्वविद्यालय को ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रदान की।



प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

भारत अब सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने में सक्षम

21वीं सदी के नए दशक में इनोवेशन के रास्ते ही किसी भी देश के लिए सफलता का दरवाजा खुलेगा। इनोवेशन के इसी सफर पर आगे बढ़ते हुए भारत अब सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने की क्षमता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हुआ...



इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है। हर चीज को वैज्ञानिक सोच से देखना चाहिए और हम कौन सी रिसर्च करें या न करें, इसके लिए हर पीढ़ी में वैज्ञानिक स्वभाव (साइंटिफिक टेपर) तैयार करना चाहिए।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच से दुनिया भर में भारत की एक नई पहचान बनी है। अब भारत विकसित देशों की तरह ऐसी श्रेणी में शामिल होने वाला देश बन गया है जो न सिर्फ सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने में भी सक्षम है बल्कि उद्योगों और संस्थानों के बीच ऐसा समन्वय का सेतु बना है जिससे विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में ही अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर रही हैं। रिसर्च की महत्ता पर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव- 2021 के उद्घाटन पर विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के रास्ते आगे बढ़ने का रोडमैप सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, “इतिहास से लेकर आज तक जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है वह देश उतना ही आगे बढ़ा है। भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। रिसर्च और इनोवेशन से ही हम ब्रांड इंडिया को मजबूत कर सकते हैं।”

काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) के 75 साल पूरे होने पर आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने नेशनल अटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया। नेशनल एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स लैबोरेट्री की आधारशिला रखी।

:0000000003
SECS

ऐसे समझें नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का फायदा

- साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82° 30' पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है।
- नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुरूप 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता देता है।
- यह न सिर्फ इसरो जैसी संस्थाओं के लिये बड़ी मदद होगी बल्कि बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, सहित कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- भारतीय निर्देशक द्रव्य प्राणाली व नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लैबोरेट्री अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लैब में जांच और मापांकन के लिए शुरु की गई है। इसे सीएसआईआर और नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी ने तैयार किया है। इससे सोने की शुद्धता की तरह मापन में शुद्धता और सटीकता तय होती है।
- नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लैबोरेट्री में उन उपकरणों की क्वालिटी चेक की जाएगी जिसके जरिए वायु और औद्योगिक प्रदूषण और उत्सर्जन की जांच की जाती है।



प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें



वंदे भारत एक्सप्रेस: स्वदेशी से गति की उड़ान भरता देश

भारत में रेलवे गति और सुरक्षा के साथ सुविधा के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को पहली पूर्णतः स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। भारत सरकार 2022 के अंत तक 44 अन्य वंदे भारत ट्रेन उतारने का लक्ष्य रखकर तेजी से आगे बढ़ रही है अब रेलवे भारत में बनी ट्रेनों से विकास की गति को दे रहा नए आयाम...

“

पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर होता था ताकि चुनावों में फायदा मिल सके। पटरियों या रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर निवेश नहीं किया गया। 2014 के बाद हमने कार्यशैली और सोच बदली। अलग से रेल बजट की व्यवस्था को खत्म करने के साथ ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। रेल ट्रेक पर निवेश किए, मानवरहित फाटक खत्म किए। हाईस्पीड ट्रेन बनाई। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें भी चल रही हैं और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हुई है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय रेल ने पिछले छह सालों में विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे वो, स्टेशन से लेकर डिब्बों के भीतर तक साफ-सफाई हो या बायो-डिग्रेडेबल शौचालय, खाने-पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हो या टिकट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था, तेजस एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर विस्टा-डोम कोच का निर्माण, भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिक हो रही है और भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 44 अन्य वंदे भारत ट्रेन उतारने का लक्ष्य पूरा करने के लिए चेन्नई स्थित एकीकृत कोच फैक्ट्री के साथ तीन कोच फैक्ट्री में निर्माण पूरा करने का फैसला किया है।

वंदे भारत: भारत की सबसे तेज ट्रेन

नई दिल्ली-वाराणसी

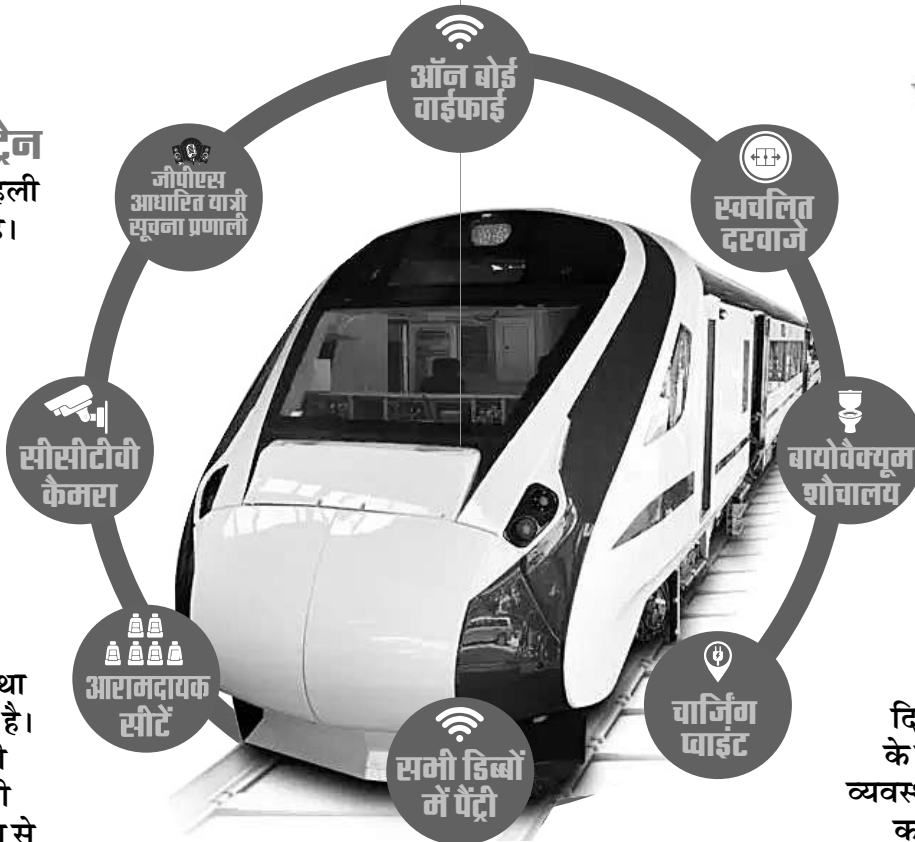
कुल दूरी	अधि.गति	अवधि
752 किमी	160 किमी	08 घंटे

नई दिल्ली-जम्मू-तवी

कुल दूरी	अधि.गति	अवधि
577 किमी	160 किमी	08 घंटे



इंजन रहित ट्रेन
यह भारत की पहली
इंजन रहित ट्रेन है।



री-जेनरेटिव
ब्रेक प्रणाली
30%
इलेक्ट्रिक ऊर्जा
की बचत होती है

प्रकाश की व्यवस्था

प्रकाश की व्यवस्था दो तरह से की गई है। एक डिब्बे में सभी के लिए और दूसरी हर सीट पर अलग से प्रकाश की व्यवस्था



दिव्यांगों के लिए विशेष

दिव्यांगों की सुविधा के लिए ट्रेन में विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

भारतीय ट्रेनों की बढ़ी रफ्तार

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 508 किमी लंबे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को 2023 तक पूरा कर लिया जाए। यह परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज दो घंटों में पूरी हो सकेगी। यह ट्रेन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। राष्ट्रीय रेल योजना के एक हिस्से के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 को लॉन्च किया गया है-

- भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रेकिंग। जीक्यू/जीडी मार्गों पर सभी स्तर के क्रॉसिंग समाप्त करना। दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर गति को 160 किमी/घंटा तक बढ़ाना।

- स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्णिम जीक्यू / जीडी मार्गों पर गति 130 किमी/घंटा तक बढ़ाना। दिल्ली-वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल से संबंधित सर्वेक्षण जारी।

- मालगाड़ियों की औसत गति को वर्तमान के 22 किलोमीटर प्रतिघंटा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा करना।

- ईस्ट कोस्ट, ईस्ट-वेस्ट और नार्थ- साउथ नाम के तीन समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की पहचान की गई है। पीईटीएस सर्वेक्षण पहले से जारी है। दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) लक्ष्य के लिए लोकोमोटिव जरूरतों का आकलन करना।



आत्मनिर्भर भारत : सशक्त भारत

भारतीय जनमानस में मालगाड़ियों को लेकर आम धारणा रही है कि इसके चलने और गंतव्य तक पहुंचने का कोई समय नहीं होता है। हालांकि, मोदी सरकार ने इस अवधारणा को बदला है। औसत 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले माल गाड़ी भी अब 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू भाऊपुर - न्यू खुर्जा खंड और पूर्वी समर्पित मालदुलाई गलियारे के संचालन नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को पश्चिमी समर्पित माल दुलाई गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लांग हॉल कंटेनर ट्रेन आपरेशंस (1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन) को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यानि डिब्बे के उपर डिब्बे, वो भी डेढ़ किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

- न्यू भाऊपुर-न्यू खुर्जा पर मालगाड़ियों की रफ्तार पूर्व औसत से करीब तीन गुना 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई। पिछले 5-6 साल के कठिन परिश्रम से साकार हुए समर्पित माल दुलाई गलियारा प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।
- दो समर्पित माल दुलाई गलियारे में शामिल पूर्वी लुधियाना से दनकुनी गलियारे पर कोयला खदान, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर जुड़े हैं। जिसके फीडर रूट भी बन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से दादरी तक पश्चिमी समर्पित माल दुलाई गलियारा है। यहां मुंद्रा, कांडला, पिपावाव, डावरी और हजीरा जैसे बंदरगाहों को फीडिंग मार्गों से जोड़ा जाएगा।
- इन माल दुलाई गलियारे के आसपास दिल्ली-मुंबई और अमृतसर-कोलकाता का औद्योगिक गलियारा विकसित किया

जा रहा है। इसी तरह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे की भी योजना बनाई जा रही है।

- भारत अब आधुनिक रेलगाड़ियां बनाने के साथ उनका निर्यात भी कर रहा है। वाराणसी विद्युत इंजन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, रायबरेली में निर्मित रेल कोच अब निर्यात किए जाते हैं।
- मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ने से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की लागत घटेगी। इसका निर्यातकों को फायदा होगा। निवेश और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग, व्यवसायी, किसान लाभान्वित होंगे। औद्योगिक रूप से पिछड़ा पूर्वी भारत भी विकास में बराबर की भागीदारी वाला कदम बढ़ाएगा।



रेवाड़ी-न्यू मदार रेल खंड के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें



न्यू भाऊपुर - न्यू खुर्जा खंड रेल खंड के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक-इन इंडिया परिकल्पना पर गाड़ी के ज्यादातर हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया। इस तरह ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ रेल गाड़ी के जरिए मध्यम तेज गति वाली भारतीय रेल के मेक-इन-इंडिया प्रयास का सपना साकार

हुआ। गाड़ी का निर्माण महज 18 महीनों में चेन्नई के एकीकृत रेल कोच फैक्ट्री में किया गया। कम से कम खर्च में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यात्री सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के मामले में यह गाड़ी वैश्विक रेल कारोबार में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। ●

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा

अंत्योदय के मूलमंत्र और सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की भावना के प्रति समर्पित केंद्र सरकार ने दशकों तक उपेक्षित जम्मू-कश्मीर में विकास को नई रफ्तार दी है। भारत सरकार की किसी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार होगा कि औद्योगिक विकास को जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा। इसके लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत अगले 15 वर्ष के लिए 28,400 करोड़ रु. की प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में खुलेंगे विकास के नए द्वार

- **फैसला:** जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये की नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के तहत 1,123.84 करोड़ रु. दिए गए हैं।
- **प्रभाव:** जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार। यह पहल विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रमुखता से बढ़ावा देगा। जम्मू-कश्मीर की आयात पर निर्भरता को कम करने और निर्यात की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। नई योजना को एमएसएमई की बड़ी इकाईयों व छोटी इकाईयों दोनों के लिए आकर्षक बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को 2020-21 से 2036-37 के दौरान 28,400 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके तहत ऐसे दिए जाएंगे प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश को होगा लाभ:

- यह योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर विशेष फोकस देकर जम्मू कश्मीर के मौजूदा औद्योगिक इकोसिस्टम में व्यापक बदलाव लाएगी।
- प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ लगभग 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। औद्योगिकीकरण होने से होगा कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, मछली व पशुपालन डेयरी उद्योग में रोजगार का सृजन।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए निवेश पर जोन ए और जोन



बी में क्रमशः 5 करोड़ रु. और 7.5 करोड़ रु. तक के पूंजी निवेश को प्रोत्साहन।

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए 500 करोड़ रु. तक की ऋणा राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का केंद्रीय पूंजीगत ब्याज अनुदान।
- 10 वर्षों के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए वास्तविक निवेश के पात्र मूल्य का 300 प्रतिशत जीएसटी लिंकड प्रोत्साहन।
- सभी मौजूदा इकाईयों के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ रु. तक की राशि 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) ब्याज अनुदान। नए निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा।
- इससे संपूर्ण जम्मू-कश्मीर निवेश का पसंदीदा स्थान बनकर उभरेगा और औद्योगिक विकास के वातावरण का निर्माण होगा।
- इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए जम्मू-कश्मीर को सक्षम करना है।

अपनी माटी, अपना देश

मिशन आत्मनिर्भरता में जुटे प्रवासी भारतीय



देश की संस्कृति और गौरव को अपने साथ ले जाकर दुनिया भर में भारत को स्थापित करने वाले प्रवासी और भारतीय मूल के लोग अब अपनी माटी का कर्ज चुकाने को आतुर हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर इसी संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने में जुटे और इस मिशन में ब्रांड इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बने देश-दुनिया में बसे प्रवासी भारतीय

“

आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना विश्वास है तो इसका कारण आप प्रवासी भारतीय हैं। आप जहां भी गए आपने भारतीयता का प्रसार किया है। भारत ने दुनिया पर कभी भी कुछ थोपा नहीं, बल्कि आपने विश्व की दृष्टि को भारत के प्रति जिज्ञासु बनाया है।

— पीएम मोदी, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर



भारत के आर्थिक इतिहास में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐतिहासिक कदम है, जो 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। इसी सोच को साकार करने में प्रवासी भारतीय भी अपनी माटी की खुशबू देश-दुनिया में बिखेरने को तैयार हैं। जिसकी झलक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में दिखी। इस समारोह में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्मिनिया के एनजीओ को तो मेडिसिन क्षेत्र में आजरबाइजान की डॉ. रजनी चंद्रा डि'मेलो, सामुदायिक सेवा के लिए फिजी के साई प्रेमा फाउंडेशन समते 30 प्रवासी और भारतीय मूल के व्यक्तियों को दुनिया में भारत के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व के लिए सम्मानित किया गया।



प्रवासी भारतीय दिवस

9 जनवरी 1915। यानी आज से 106 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से एक वकील अंग्रेजों का सामना कर भारत लौटे मोहनदास करमचंद गांधी। जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता और महात्मा गांधी के नाम से जाना गया। उन्होंने न सिर्फ सत्याग्रह-अहिंसा का पाठ दुनिया का सिखाया, बल्कि ये भी बताया कि अहिंसा के रास्ते से भी विजय हासिल की जा सकती है। वर्ष 2003 से उनकी याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मकसद है- देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान देना। साल 2015 से इसके फॉर्मेट में बदलाव कर इसे थीम आधारित किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम थी 'आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान' तो आइए जानते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में ...

कौन हैं प्रवासी भारतीय

 **1.87** | प्रवासी भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में

ऐसे लोग सबसे ज्यादा अमेरिका में हैं। करीब 31.80 लाख भारतीय मूल के लोग अमेरिकी नागरिक हैं।

- भारतीय न केवल तमाम देशों में बतौर प्रवासी रहते हैं, बल्कि वहां के नागरिक भी हैं। ऐसे लोग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं।
- ये लोग भारतीय मूल के वे विदेशी नागरिक हैं, जो या तो खुद कभी भारत के नागरिक थे या उनके माता-पिता, दादा-दादी, पति या पत्नी में से कोई भारतीय नागरिक है या थे।
- इंदिरा नुई से लेकर सुंदर पिचाई हों या सत्या नडेला से कल्पना चावला। दुनियाभर में प्रवासी भारतीयों ने अपने देश को गर्व करने का मौका दिया है।

अब भारतीय क्षमता को वैश्विक पहचान मिल रही है। देश न केवल आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है बल्कि एक सैन्य सुपर शक्ति के रूप में भी उसे मान्यता मिली है। इसने आइटी से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना ली है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तौर पर 29.87 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के कारण, उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था वी आकार में यानि नीचे आने के बाद बहुत तेजी से उपर की ओर जा रही है।

इस विकास यात्रा में भारतीय प्रवासी की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के संबोधन में किया। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के थीम के तौर पर 'आत्मनिर्भर भारत में योगदान' पर प्रधानमंत्री ने कहा, "देश जैसे-जैसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रवासी

प्रवासी भारतीयों से संबंधों को नई दिशा देते प्रधानमंत्री मोदी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से प्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। वे मोदी को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं जो भारत में बदलाव लाने में सक्षम हैं।
- हर विदेशी दौरे में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्कावयर गार्डन से लेकर सिडनी के अल्फॉस एरेना तक, मॉरीशस से शंघाई तक, हर जगह भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है।
- एक अत्यंत आवश्यक सुधार पीआईओ और ओसीआई को एक करने का किया जिसका प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया है। वीजा नियमों में छूट दी गई। प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।

भारतीयों की प्रमुख भूमिका है क्योंकि भारत के उत्पादों में उनके उपयोग से भारतीय उत्पादों के प्रति अधिक विश्वास पैदा होगा।" जब आप 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को अधिक इस्तेमाल करेंगे तो आपके इर्द-गिर्द रहने वालों में भी इसको लेकर विश्वास बढ़ेगा। चाय से लेकर कपड़ा और थैरेपी तक, ये कुछ भी हो सकता है। खादी दुनिया में आकर्षण का एक केन्द्र बन रही है। इससे आप भारत के निर्यात की मात्रा तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की समृद्ध विविधता को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया में गरीब से गरीब तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण समाधान पहुंचाने का जरिया बनेंगे।

इसके अलावा, प्रवासी भारतीय की सहायता, विशेषज्ञता, निवेश और वैश्विक नेटवर्क आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेंगे। इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और इसके कुछ नतीजे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स,



ईज ऑफ ट्रैवल और इस जैसे अन्य जगहों पर भारत की रैंकिंग में सुधार के रूप में सामने आ रहा है जिससे वैश्विक समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। चार नए लेबर कोड, कृषि सुधार और बेतहर बुनियादी सुविधाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हालांकि, भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे की भावना 'सैकड़ों हाथों से अर्जन करो, हजारों हाथों से बांटो है।' लाखों भारतीयों की कड़ी मेहनत से भारत में बनने वाले उत्पाद और भारत में विकसित होने वाले समाधान से पूरी दुनिया को फायदा होगा। दुनिया कभी भी Y2K (वाय-टू-के) के समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार विश्व को चिंतामुक्त किया था उसे नहीं भूल सकती है। भारत अवसर में बदलने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के अहम बिंदु

- मेड इन इंडिया उत्पादों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो इससे दुनिया भर में उन उत्पादों को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मेड इन इंडिया के उत्पादों और समाधानों से पूरी दुनिया को लाभ होगा। भारत के फार्मा उद्योग ने इस क्षमता को प्रदर्शित किया है।
- आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने को आगे बढ़ रहा है तो ब्रांड इंडिया को मजबूती देने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है।
- आज भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम और टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में दुनिया में अग्रणी है, महामारी के दौरान कई नए युनिर्कॉन और टेक स्टार्ट अप शुरू किए गए थे। दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नया पोर्टल 'रिश्ता' शुरू किया है।



प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

भारत के विकास और सभ्यता के सहयात्री



भारतीय मूल के नागरिकों ने राजनीति हो या नवाचार और तकनीक अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले सांसद बने थे तो हाल ही में भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है। इसी तरह सूरीनाम में राष्ट्रपति का पद भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने संभाला हुआ है तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व प्रविंद जगन्नाथ कर रहे हैं। इसी तरह ब्रिटेन में गृहमंत्री की जिम्मेदारी प्रीति पटेल संभाल रही हैं। अमेरिका, गयाना, सिंगापुर, फिजी, बिसेसर त्रिनिनाद एवं टोबैगो का नेतृत्व भी भारतीय मूल के लीडर्स कर चुके हैं। इसी तरह प्रबंधन में सुंदर पिचई, सत्या नडेला, इंदिरा नुई, शांतुन नारायण, अजय बंगा सहित तमाम भारतीय मूल के लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं। विदेशों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। इस बार न्यूजीलैंड की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष डॉ. मुकेश अघी सहित 30 लोगों को सम्मान दिया गया।

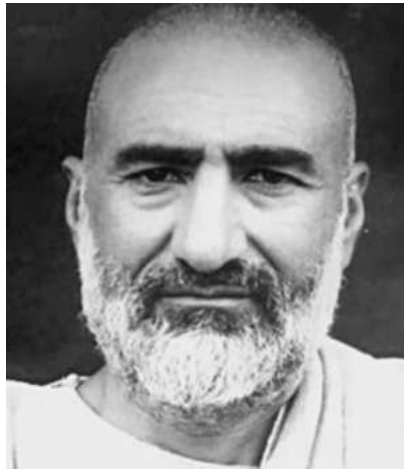
भारत से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले 'सीमांत गांधी'

महात्मा गांधी के बेहद करीबी खान अब्दुल गफ्फार खान ना केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर थे बल्कि वह अहिंसा के भी कट्टर समर्थक थे। उनकी जयंती पर भारत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है...

दस्तावेजों के अनुसार तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक पाकिस्तानी नागरिक थे लेकिन दिल से वह एक सच्चे हिन्दुस्तानी थे। उन्हें 1987 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसके वह असली हकदार थे। वह ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक शिक्षाविद, गांधीवादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर और एकीकृत भारत के मुखर समर्थकों में भी थे। वह धर्म के आधार पर द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। जब कांग्रेस ने एक मुस्लिम बहुल देश में रूप में पाकिस्तान के मांग को स्वीकार कर लिया तब उन्होंने खुद को छला हुआ महसूस करते हुए कांग्रेस नेताओं से कहा था, “आपने हमें भेड़ियों की तरफ फेंक दिया है।”

खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रति भारतीयों के प्रेम, मान और सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था, “मेरा सौभाग्य रहा है कि बचपन में खान अब्दुल गफ्फार खान जी के चरण छूने का मुझे अवसर मिला था। मैं इसे अपना गर्व मानता हूँ।”

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अगुवा रहे गफ्फार खान ने 1929 में कांग्रेस के सत्र



जन्म : 6 फरवरी 1890
मृत्यु : 20 जनवरी 1988

में भाग लेने के तुरंत बाद पश्तूनों के बीच खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया। इस संगठन ने भारत की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया और पश्तूनों की राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश की। गांधीजी के विचारों और सुझावों से प्रभावित गफ्फार खान उनके करीबी सहयोगियों में से एक थे। गफ्फार खान को उनके करीबी अमीर चंद बोम्बाल ने सीमांत गांधी के उपनाम से नवाजा था।

गफ्फार खान का व्यक्तित्व कितना विशाल था, उसे ब्रिटिश नागरिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता म्यूरियल लेस्टर के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने 1939 में गफ्फार खान के बारे में गांधी

जी को लिखा है, “खान अब्दुल गफ्फार खान को अब भली-भांति जान लेने के बाद मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जहां तक दुनिया के अद्भुत व्यक्तियों से मिलने का सवाल है, इस तरह का सौभाग्य मुझे अपने जीवन में शायद कोई और नहीं मिलने वाला है। वे ‘न्यू टेस्टामेंट’ की सौम्यता से युक्त, ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ के राजकुमार हैं। वे कितने भगवत्परायण हैं! आपने उनसे हमारा परिचय कराया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले गफ्फार खान ने आजादी के बाद पाकिस्तान में रहने का निर्णय लिया था। उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। 8 मई 1948 को पाकिस्तान आजाद पार्टी का गठन किया जो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय विपक्षी दल था। पार्टी ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने और अपनी विचारधारा में गैर-सांप्रदायिक होने की शपथ ली। 1984 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1985 में उन्होंने आखिरी बार भारत की यात्रा की। 1988 में नजरबंद रहने के दौरान पेशावर में उनका निधन हो गया और अफगानिस्तान के जलालाबाद में उन्हें सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया। ●

पर्यावरण बचाने की अनोखी पहल

हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर ग्रह छोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन को साकार करने में लगी हैं पूजा बाड़मिकर और 'बेंगलुरु हुडुगुरु' नामक एक संगठन। पूजा जहां अपने स्टार्टअप के जरिए पुराने टायर से फुटवियर बनाने के काम में जुटी हुई हैं वहीं, 'बेंगलुरु हुडुगुरु' संगठन पेड़ों में लगे कील-कांटों को निकालने के काम में लगी हुई है। इस तरह ये पर्यावरण बचाने के मुहिम में शामिल होकर लोगों के लिए पेश कर रहे हैं उदाहरण...

पुराने टायर से फुटवियर बनाने का दूढ़ा नयाब तरीका



पुराने और खराब टायर से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पूजा बाड़मिकर ने एक नयाब तरीका दूढ़ा निकाला है। पूजा इन बेकार टायरों से फुटवियर बनाने का काम करती हैं। पूजा इसके लिए कार-बस और ट्रक के खराब हो चुके टायर का इस्तेमाल करती हैं। पूजा का कहना है कि दुनिया भर में हर साल करीब एक करोड़ टायर कबाड़ में फेंक दिए जाते हैं। इसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में वह पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहती हैं। ऐसे में उनके दिमाग में पुराने टायरों के रिसाइकलिंग के बारे में आइडिया आया। पूजा के इस सराहनीय कदम के चलते उन्हें महिला उद्यमिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फुटवियर बनाने के बिजनेस में आने से पहले पूजा एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी। पूजा ने अक्षय ऊर्जा में परास्नातक किया है। ऐसे में पर्यावरण के लिए कुछ करने का विचार हमेशा उनके दिमाग में आता-जाता रहता था। बाद में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की खातिर नौकरी छोड़ दी और टायर से फुटवियर बनाने के पेशे में कदम रखा। यह काम शुरू करने से पहले उन्होंने काफी शोध किया और स्थानीय मोचियों की मदद से इस काम की शुरूआत की। इसमें पूजा ने दो प्रोटोटाइप बनाए। वे अपने फुटवियर ब्रांड 'निमितल' के जरिए पिछले दो सालों से यह काम कर रही हैं। उनका मानना है कि टायर से फुटवियर बना कर बाजार में प्लास्टिक की सप्लाई को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रि-साइकलिंग एक अच्छा विकल्प है। अपने स्टार्टअप के जरिए उन्होंने एक आत्मनिर्भर महिला का उदाहरण भी पेश किया है। ●

पेड़ से कील निकाल दे रहे जागरूकता का संदेश



भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करता रहा है। साथ ही विभिन्न शहरों में रहने वाले लोग भी सरकार की उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। इसी तरह की एक पहल 'बेंगलुरु हुडुगुरु' नामक एक संगठन ने की है। इस समूह के सदस्य पेड़ों को बचाने के लिए उसमें लगे कील-कांटों को निकाल फेंकने के लिए पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। समूह के सदस्य यह काम सप्ताहंत में करते हैं। दरअसल, शहर में कीलों से पेड़ों और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। बेंगलुरु शहर को अपनी हरियाली और पर्यावरण के कारण गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है।

समूह की एक सदस्य कृति जोशी ने बताया कि एक बार एक कील उनके पांव में घुस गया और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि, उन्हें इसके लिए बाद में तीन बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऐसे में उनके दिमाग में विचार आया कि अगर यह इंसान के शरीर में जहर फैला सकता है तो यह निश्चित रूप से बेजुबान पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा होगा। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में पेड़ों को कीलों से आजादी दिलाने का निर्णय लिया। इस अभियान के दौरान ऐसे कुछ मामले सामने आए जब एक पेड़ से एक किलो से अधिक कीलें बाहर निकाली गईं। ●



Narendra Modi

देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई।

Rajnath Singh

भारत की प्रगति के पहिए अब और तेज़ी से घूमेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने रेलवे के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करके देश में माल ढुलाई की प्रक्रिया को नई गति प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्रीजी और रेल मंत्री श्री @PiyushGoyal को बधाई।

Amit Shah

यह योजना जम्मू-कश्मीर में समृद्धि का एक नया सवेरा लाएगी। इससे अभूतपूर्व निवेश आकर्षित होगा व लगभग 4.5लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

इससे युवाओं का कौशल विकास होगा व वर्तमान उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे जम्मू-कश्मीर देश के अन्य क्षेत्रों के समान सक्षम बन पाए।



Nitin Gadkari

ग्रामीण इकोंमि की बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए हम खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नए-नए इन्वोवेशन के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में आज केवीआईसी (KVIC) के माध्यम से गाय के गोबर से बने एंटी-वायरल 'प्राकृतिक पेंट' को केंद्रीय मंत्री श्री @girirajsinghbjp जी एवं केंद्रीय राज्यमंत्री श्री @pcsarangi जी की उपस्थिति में लॉन्च किया।



Kiren Rijju

I'm happy to share that govt is leaving no stone returned to ensure our athletes get the best support. Bringing world acclaimed sports scientist Dr Genadijus Sokolovas to work with our swimmers is a step in that direction. Top swimmers including Michael Phelps have consulted him



Tedros Adhanom Ghebreyesus

#India continues to take decisive action & demonstrate its resolve to end #COVID19 pandemic. As the world's largest vaccine producer it's well placed to do so. If we #ACTogether, we can ensure effective & safe vaccines are used to protect the most vulnerable everywhere @narendramodi

प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी के इस दौर में भारत ने दिखाया कि हमारा सामर्थ्य और क्षमता क्या है

भारतीय टीकों पर दुनिया की निगाहें: मोदी

प्रवासी सम्मेलन

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के चौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन देते हुए कहा कि पूरी दुनिया को भारत की वैक्सिन का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने निम्नलिखित को कहा कि कोरोना काल में भारत की ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान प्रवासी भारतीयों के योगदान को खामोश पर सराहा।



नई दिल्ली में निम्नलिखित को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।

निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं और जो

भारत में लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत और जीवंत

प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत को अजानी मिली, तब कहा जाता था कि यह नहीं देना है, कम पड़ा लिखा देना है और वह खिल जाएगा, टूट जाएगा। वह भी कहा जाता था लोकतंत्र तो क्या संभल ही नहीं है। लेकिन आज सचवाइ यह है कि भारत एकजुट है और भारत ही वह स्थान है जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत और जीवंत है। मोदी ने कहा कि हमने कभी दुनिया पर कोई चीज नहीं खोबी, न ही खोबने के बारे में सोचें बल्कि भारत के बारे में जिज्ञास फेदा की है।



जयशंकर ने भारतीय समुदाय को आमंत्रित किया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वायरस के कारण उद्वेगपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रवासी भारतीयों से निम्नलिखित के माध्यम से निम्नलिखित के निर्माण में हिस्सा लेने के लिए निम्नलिखित को भारतीय समुदाय को आमंत्रित किया। जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों से निम्नलिखित के माध्यम से निम्नलिखित के निर्माण में हिस्सा लेने के लिए निम्नलिखित को भारतीय समुदाय को आमंत्रित किया।

वैक्सिन के लिए लाभार्थियों के मोबाइल आधार से जोड़ें

निर्देश

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र ने संविधान को कहा कि कोरोना टीके को आपूर्ति को निगरानी के लिए एक अनिवार्य फ्लैगशिप को-पिन होगा। यह टीकाकरण अभियान का आधार होगा और यह नागरिक केंद्र होगा। केंद्र ने राश्यों को कहा कि वे लोगों के आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करें ताकि टीकाकरण के लिए परामर्श भेजने में सुविधा हो।



वास्तविक समय में डेटा हासिल करने पर जोर

राश्यों ने टीकाकरण संबंधी डेटा वास्तविक समय में हासिल करने के महत्व को रेखांकित किया। अभियान के लक्ष्यार्थियों को विनाह रूप से पहचाना जाए। मोबाइल नंबर को आधार के साथ जोड़ें जिससे बाढ़ के संघर्ष के लिए परामर्श सुविधा हो।

50 से अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता

नेताजी की 125वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाएगा केंद्र

जयशंकर ने कहा, जब भारत को अजानी मिली, तब कहा जाता था कि यह नहीं देना है, कम पड़ा लिखा देना है और वह खिल जाएगा, टूट जाएगा। वह भी कहा जाता था लोकतंत्र तो क्या संभल ही नहीं है। लेकिन आज सचवाइ यह है कि भारत एकजुट है और भारत ही वह स्थान है जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत और जीवंत है। मोदी ने कहा कि हमने कभी दुनिया पर कोई चीज नहीं खोबी, न ही खोबने के बारे में सोचें बल्कि भारत के बारे में जिज्ञास फेदा की है।

जयशंकर ने कहा, जब भारत को अजानी मिली, तब कहा जाता था कि यह नहीं देना है, कम पड़ा लिखा देना है और वह खिल जाएगा, टूट जाएगा। वह भी कहा जाता था लोकतंत्र तो क्या संभल ही नहीं है। लेकिन आज सचवाइ यह है कि भारत एकजुट है और भारत ही वह स्थान है जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत और जीवंत है। मोदी ने कहा कि हमने कभी दुनिया पर कोई चीज नहीं खोबी, न ही खोबने के बारे में सोचें बल्कि भारत के बारे में जिज्ञास फेदा की है।

पिछली छमाही में वस्तुओं का व्यापार घाटा 36% कम हुआ

पीएम के 'लोकल फॉर लोकल' अभियान का दिखने लगा असर

नई दिल्ली | आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'लोकल फॉर लोकल' नारे का असर रि-धरि दिखने लगा है। विशेषकर छह छह महीनों में व्यापार घाटे हुई गिरावट इसकी गवाही दे रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में तुओं का व्यापार घाटा 36% कम हुआ।

मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सिनेशन रणनीति पर चर्चा करेंगे मोदी

नई दिल्ली, (आईएनएस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सिनेशन की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा होगी। इस अहम मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सिनेशन के लिए अपनी तैयारियों की रिपोर्ट लेकर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वरचुअल माध्यम से यह बैठक शाम चार बजे से शुरू होगी। भारत में दो मेड इन इंडिया वैक्सिन बन चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोलिसि



राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा होगी

लगातार मुख्यमंत्रियों से चर्चा के जरिए सुझाव लेते थे, अब उसी तरह टीकाकरण अभियान के दौरान मुख्यमंत्रियों से चर्चा के लिए



भारत को किला !

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने के साथ नारी मुक्ति आंदोलन को नई दिशा देने वाली सरोजिनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल भी थीं। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मीं सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने खुद भारत को किला की उपाधि दी थी।

“
एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम
उस देश के आदर्शों में निहित होता है।
”

सरोजिनी नायडू